

प्रेषक,

ओम प्रकाश  
प्रमुख सचिव,  
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,  
प्रशिक्षण, विभाग,  
उत्तराखण्ड, हल्द्वानी।

प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा अनुभाग-2

देहरादून : दिनांक 29 फरवरी, 2016

विषय: राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खेतीखान के आवासीय/अनावासीय भवनों के फेज-1 में निर्माण कार्यों की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया अपने पत्र संख्या-9888/डीटीईयू/भूमिभवन/0450/खेतीखान/2015, दिनांक 08 जुलाई 2015, तथा आंगणनों के सम्बन्ध में उत्तराखण्ड पेयजल संस्थान विकास एवं निर्माण निगम के पत्र संख्या 2101/टी0ए0सी0/39, दिनांक 06.06.2015 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खेतीखान के आवासीय/अनावासीय भवनों के प्रथम फेज में निर्माण हेतु ₹15.80 लाख के आंगणन उपलब्ध कराये गये हैं, जिसको शासनादेश संख्या-359/XXVII(1)/2015, दिनांक 23 मार्च, 2015 के अनुपालन में विभागीय टी0ए0सी0 द्वारा परीक्षणोंपरान्त ₹8.38 लाख औचित्यपूर्ण पाया गया। इस सम्बन्ध में वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-400/XXVII(1)/2015, दिनांक 01 अप्रैल, 2015 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खेतीखान के अनावासीय एवं आवासीय भवनों निर्माण हेतु प्रथम किश्त के रूप में ₹8.38 लाख (रुपये आठ लाख अड़तीस हजार मात्र) की धनराशि को व्यय करने का श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति निम्न शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं:-

- (1) कार्य करने से पूर्व मदवार दर विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/ अनुमोदित दरों के आधार पर तथा जो दरें शेड्यूल ऑफ रेट्स में स्वीकृत नहीं हैं, अथवा बाजार भाव से ली गयी हों, की स्वीकृति नियमानुसार अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।
- (2) आवासीय एवं अनावासीय दोनों कार्यों का पृथक-पृथक ड्राईंग तैयार किया जायेगा तथा निदेशक प्रशिक्षण से नियमानुसार आवश्यकता के अनुरूप मानचित्र तैयार कर अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा। कार्य करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि निर्माण कार्य आवश्यकता के अनुरूप एवं मानकों के अनुसार किये गये हैं तथा इस पर सक्षम स्तर का अनुमोदन निर्धारित प्रक्रियानुसार प्राप्त कर लिया गया है। किसी भी परिस्थिति में निर्माण कार्य आवश्यकता से अधिक नहीं होना चाहिए। कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम अधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी आवश्यक होगी तथा उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (3) कार्य पर उतना ही व्यय किया जाए जितनी राशि स्वीकृत की गयी है। स्वीकृति धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।
- (4) कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्ये-नजर रखते हुए एवं लो0नि0वि0 द्वारा प्रचलित दरो/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित करने से पूर्व पूर्ण कराना करना सुनिश्चित करें।



- (5) कार्य करने से पूर्व उच्चाधिकारियों एवं भूगर्भवेत्ता (कार्य की आवश्यकतानुसार) से कार्य स्थल का भली-भांति निरीक्षण अवश्य करा लिया जाए तथा निरीक्षण के पश्चात् एन0सी0वी0टी0 के मानकों के अनुसार कार्य कराया जाए।
  - (6) वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-475/XXVII(7)/2008, दिनांक 15.12.2008 के अनुसार निर्धारित प्रारूप पर कार्यदायी संस्था से एम0ओ0यू0 हस्ताक्षरित कराया जाना अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जायेगा। इसका उत्तरदायित्व निदेशक का होगा।
  - (7) समस्त प्राविधानों पर कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर सक्षम अधिकारी से अनुमोदन अवश्य प्राप्त कर लिया जाए।
  - (8) उक्त कार्य के प्रगति की निरन्तर समीक्षा करते हुए इन्हें समयबद्ध ढंग से निर्धारित समय सारिणी के अनुसार पूर्ण जाना सुनिश्चित किया जाय। विलम्ब के कारण आगणन के पुनरीक्षण पर विचार नहीं किया जायेगा।
  - (9) निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से आवश्यक करा लिया जाय तथा उपयुक्त सामग्री को ही प्रयोग में लाया जाए। कार्य की प्रगति एवं गुणवत्ता के सम्बन्ध में थर्ड पार्टी चेंकिंग की व्यवस्था की जाय जिसके सापेक्ष होने वाला व्यय देय सेन्टेज चार्ज के सापेक्ष वहन किया जायेगा तथा गुणवत्ता का समस्त उत्तरदायित्व निर्माण एजेंसी का होगा।
  - (10) आगणन में प्राविधानित डिजाइन एवं मात्राओं हेतु सम्बन्धित कार्यदायी संस्था पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगे। मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या: 2047/XIV-219(2006), दिनांक 30.05.06 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
  - (11) स्वीकृत विस्तृत आगणन के प्राविधानों एवं तकनीकी स्वीकृति के आगणन के प्राविधानों में परिवर्तन (केवल अपरिहार्य स्थिति की दशा में ही) करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की सहमति अनिवार्य रूप से प्राप्त कर ली जाये।
  - (12) कार्य हेतु यदि किसी अन्य समरूप कार्य हेतु पूर्व में कराई गई डिजाइन/मानक पूर्ण रूप से अथवा आंशिक रूप से विषयगत कार्य हेतु प्रयोग की जा सकती है या वर्तमान कार्य में एक भाग की डिजाइन/मानक पूर्ण रूप से अथवा आंशिक रूप से विषयगत कार्य हेतु प्रयोग की जा सकती है, तो मितव्ययता की दृष्टि को ध्यान में रखते हुये तदनुसार कार्यवाही की जाये।
2. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2015-16 में आय-व्ययक के 'अनुदान संख्या 16' के अयोजनागत/पूंजीगत पक्ष के लेखाशीर्षक "4216-आवास पर पूंजीगत परिव्यय, 80-सामान्य-आयोजनागत-001-निदेशन तथा प्रशासन-07-राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का सुदृढीकरण-00-24-वृहद निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।
3. यह आदेश शासनादेश संख्या 183/XXVII-I/2012 दिनांक 28.03.2012 द्वारा विहित व्यवस्था के क्रम में [www.cts.uk.gov.in](http://www.cts.uk.gov.in) से सॉफ्टवेयर के माध्यम से उपरोक्त स्वीकृति/बजट आवंटन हेतु निर्गत विशिष्ट नम्बर/अलॉटमेंट आई.डी. S1512160385 के अन्तर्गत किये जा रहें हैं।
4. यह आदेश वित्त विभाग के अ0शा0 संख्या-147(P)/XXVII(5)/2016, दिनांक 20 फरवरी, 2015-16 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

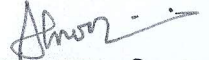
(ओम प्रकाश)  
प्रमुख सचिव।

संख्या 169 (1)/XLI-1/16-629/(प्रशि0)/2003 तददिनांकित।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. महालेखाकार, ऑडिट, उत्तराखण्ड, इन्दिरा नगर, देहरादून।
3. आयुक्त कुमायू मण्डल।
4. जिलाधिकारी चम्पावत।
5. वरिष्ठ कोषाधिकारी, चम्पावत।
6. निदेशक कोषागार एवं वित्तीय सेवायें, उत्तराखण्ड देहरादून।
7. वित्त अधिकारी, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, हल्द्वानी-नैनीताल।
8. प्रधानाचार्य, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, खेतीखान (चम्पावत)।
9. वित्त अनुभाग-5/नियोजन विभाग।
10. परियोजना प्रबन्धक, उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, लोहाघाट चम्पावत।
11. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, सचिवालय परिसर, देहरादून।
12. एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
13. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

  
(अनूप कुमार मिश्रा)  
अनु सचिव।